

- अपीलद्वारा द्वारा अधीन पेश कर निवेदन किया कि अदालत मातहत तहसीलदार राजस्व अधिकारियों द्वारा किये गये इंतकाल नं. 141 दि. 26.02.2006 को निरस्त किया जान में मुताबिक वारिस नामा के अपीलद्वारा के नाम से इंतकाल दर्ज किये जाने की आदेश दिये जाते।
2. अपील नं. 42/2015 पर दर्ज की गई व उभय रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलद्वारा की तरफ से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र शर्मा हाजिर हुए व रेस्पोंडेंट की तरफ से अधिवक्ता श्री सुभाष चन्द उपस्थित हुए।
 3. यह कि अपीलद्वारा ने दि. 06.10.2017 को न्यायालय में प्रा. पत्र देकर सुचित किया है कि प्रतिवादी नं. 1 श्रीमति गंगाकवर का देहान्त हो चुका है। अपने प्रा. पत्र में अंकित किया है कि गंगाकवर के जायज वारिस पूर्व में इस अपील में पक्षकार है। उत्तरवादियों ने इस प्रा. पत्र का कोई विरोध नहीं किया है। इसलिए अपीलद्वारा का प्रा. पत्र दि. 06.10.2017 स्वीकार जाता है तथा मृतक उत्तरवादी नं. 1 का नाम कलमखर किया जाता है।

अपीलद्वारा के अभिभाषक के द्वारा दि. 06.12.2017 को एक प्रा. पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रा. पत्र दस्तावेज अपील के साथ संलग्न करने का निवेदन किया। इस प्रा. पत्र का जबाब रेस्पोंडेंट ओमप्रकाश वगैरह ने जरिये वकील प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि अपील स्तर पर बिना विशेष कारण के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं। दायम, प्रस्तुत प्रा. पत्र के साथ जो दस्तावेजी साक्ष्य जो अपीलद्वारा ने पेश किये हैं वो फोटो प्रतियां हैं जो कानूनन साक्ष्य में बाध्य नहीं हो सकती है। अपीलद्वारा इस जबाब का कोई खण्डन नहीं कर सके।

दिनांक 13.12.2017 को रेस्पोंडेंट्स ओमप्रकाश, हनुमान, बुधराम ने एक प्रा.पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि प्रा. पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य शपथ पत्र, श्रीमति गंगाकवर पत्नी सुल्तानसिंह, अच्युतकवर, भैरुसिंह, शायर कवर, अजय कवर, बंदर कवर पुत्र-पुत्रियां सुल्तानसिंह ने दि. 3.02.2006 को पेश किया। जिसे उचित न्याय हित में पढा जाना अति आवश्यक है। प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे।

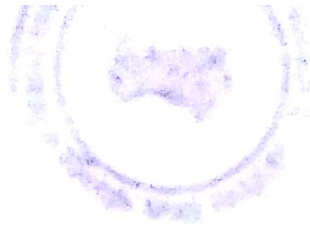
दिनांक 15.12.2017 को अपीलद्वारा भैरुसिंह आदि की तरफ से उनके अभिभाषक ने ए प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 57 भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। इस प्रा.पत्र का जबाब रेस्पोंडेंट ओम प्रकाश वगैरह ने अपने अभिभाषक के माध्यम से दि. 05.01.2018को पेश किया और प्रार्थी के प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया।

अपीलद्वारा व रेस्पोंडेंट्स के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गई। पत्रावली का गम्भीरता से अवलोकन किया गया तथा बहस के दौरान उभय पक्ष ने जो- जो नजीरे पेश की उनका भी ससम्मान अवलोकन किया गया।

अपीलद्वारा के द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र दि. 06.12.2017 आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का नियम विरुद्ध प्रस्तुत हुआ होने के कारण अस्वीकार किया जाता है तथा रेस्पोंडेंट के द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र दि. 13.12.2017 स्वीकार किया जाता है।

अपीलद्वारा के द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र दि. 15.12.2017 को कानून सम्मत नहीं होने से व धारा 57 के प्रा.पत्रों के विपरीत होने से अस्वीकार किया जाता है।

इस अपील में संलग्न प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुनना व उसका निर्णय करना कानूनन अनिवार्य है। अपीलद्वारा/प्रार्थीगण ने प्रा.पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रा. पत्र में अंकित कथनों के आधार पर हुई देरी को माफ किया जाकर अपील की सुनवाई की जावे। रेस्पोंडेंट ओमप्रकाश वगैरह ने अपने अभिभाषक के माध्यम से धारा 5 में प्रा.पत्र का जबाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रा.पत्र धारा 5 सद्भाविक नहीं है। असत्य कथनों के साथ पेश किया है। न्यायालय के समक्ष विद्व. क्लीन हेन्डेड नहीं आये हैं। प्रा.पत्र तथाकथित वसीयत का इंतकाल दर्ज होते समय सुल्तानसिंह के वारिसों के द्वारा सहमति का शपथ पत्र निस्पादित किया था। जिससे स्पष्ट होते है कि अपीलधीन आदेश की जानकारी अपीलद्वारा को प्रथम दिन से ही अच्छी तरह से थी तथा यह आदेश राजस्व तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा दि. 26.02.2006 को पारित किया है। उस आदेश के विरुद्ध यह अपील दि. 30.07.2015 को पेश की गई है व दि. 06.08.2015 को दर्ज की गई है। इस प्रकार यह अपील अपीलद्वारा के द्वारा धोर लापरवाही करते हुए पेश की है। अपने अधिकारों के प्रति पूर्णतया उदासीन रहे हैं। अपीलद्वारा द्वारा अपीलधीन आदेश के करीब साढ़े आठ वर्ष अवधि के बाद अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के बारे में कोई ठोस कारण प्रकट नहीं किए हैं। सुल्तानसिंह की मृत्यु 1987 में होने के बाद अपील 2015 में प्रस्तुत की मगर इस बीच के लगभग 28 वर्ष के समय में अपीलद्वारा द्वारा दिवसतन इंतकाल दर्ज करवाने की कोई कार्यवाई नहीं करना अपने आप में धोर लापरवाही प्रमाणित हो रही है। अपीलद्वारा के द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के संघर्ष में प्रस्तुत दस्तावेज पेश किये है वो इस प्रकार पर लागू नहीं होते हैं। उनके तथ्य भिन्न होने के कारण इस प्रकार पर



ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

(Handwritten signature)
2021/8
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀಡಬೇಕು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀಡಬೇಕು